संक्षिप्त समाचार

सीडीओ 1 जनवरी को लेंगे बैठक

संवाददाता देहरादून। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण देहरादून राजेन्द्र सेमवाल ने अवगत कराया है लोक योजना अभियान–2019 (सबकी योजना सबका विकास) मिशन अन्त्योदय सर्वे एवं जीपीडीपी निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीय स्तर मॉनिटरिंग 1 जनवरी से 6 जनवरी तक जनपद के तीन विकासखण्डों डोईवाला, रायपुर एवं कालसी के भ्रमण पर रहेगे, जिसके सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत की अध्यक्षता में 01 जनवरी को सांय 04 बजे समस्त रेखीय विभागों की एक आवश्यक बैठक विकास भवन सभागार में आहूत की गयी है।

गुरू गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर भव्य नगर संकीर्तन का आयोजन

संवाददाता देहरादून। श्री गुरू गोविंद सिंह के पावन प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में सिख समुदाय ने एक भव्य नगर संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया। जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। श्री गुरू गोंविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के मौके पर नगर के सभी गुरूद्वारों की संगत ने दून की सड़कों पर नगर संर्कीतन का आयोजन किया।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने कहा उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए

संवाददाता देहरादून। आंगनबाड़ी कार्यकत्री सेवा/मिनी कर्मचारी संगठन ने सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और उनको राज्य के अधीन सेवायोजन के तहत हितलाभ प्रदान किए जाएं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को महंगाई दर बढ़ने पर उसकी प्रतिपूर्ति वर्गीकरण के आधार पर किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों को आंगनबाड़ी साहयिकाओं से भरा जाए।

सचिवालय में लगी आग जरूरी दस्तावेज जले

अग्निकांड

अग्निकांड में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई

न्याय विभाग के जरूरी दस्तावेज और सामान जलकर राख हो गया

संवाददाता

देहरादून। सचिवालय में मंगलवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गयी। इस अग्निकांड में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई लेकिन न्याय विभाग के जरूरी दस्तावेज और सामान जलकर राख हो गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया जिससे कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आग न्याय विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह के कमरे में लगी। कमरे में जिस समय आग लगी उस समय कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। आग लगने का कारण ऐसी में शाट सर्किट होना बताया जा रहा है। जिस समय आग लगी उस समय कमरे में ऐसी चल रहा था लेकिन वहां कोई कर्मचारी या अधिकारी मौजूद नहीं था। दफ्तर के पास से गुजर रहे लोगों ने जब कमरे से धुंआ उठता

सचिवालय में आग लगने से निकलता धुंआ।

देखा तो शोर मचाया जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गयी।

मौके पर मौजूद लोगों द्वारा सचिवालय परिसर में लगे अग्निशमन यंत्रों के प्रयोग करने की कोशिश की गयी लेकिन यह यंत्र बेकार ही साबित हुए।

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियों ने इस आग पर तत्काल काबू पा लिया जिससे और अधिक नुकसान होने से बच गया। भले ही इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई हो लेकिन सचिवालय जैसे अतिसंवेदनशील और महत्वपूर्ण भवनों में इस तरह की आगजनी की घटना से कई सवाल खड़े हो गये। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अग्निशमन यंत्रों का काम न करना। जबकि इसके पुख्ता बंदोबस्त यहां होने जरूरी है।

इस अग्निकांड में कमरे में रखा सामान और अन्य जरूरी कागजात जलकर खाक हो गये। अगर दस्तावेजों की अहमियतों के हिसाब से देखा जाये तो यह बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। आग न्याय विभाग के कार्यलय में लगी। इससे यह समझा जा सकता है कि इसमें कितने जरूरी दस्तावेज रहे होंगे। अभी इसके बारे मे कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है कि इस अग्निकांड में कौन कौन से दस्तावेज जले है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।

राज्य में होने वाले ३८वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक

संवाददाता देहरादून। सचिवालय सभागार में मंगलवार को आगामी 2021 में उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रदेश में विभिन्न खेल विधाओं के आयोजन हेतु चयनित स्थलों के अवस्थापना विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सचिव खेल को निर्देश दिए कि निर्माण के दौरान इण्डियन ओलंपिक संघ एवं राष्ट्रीय खेल संघ से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें, ताकि मैदान एवं अन्य अवस्थापना कार्य मानक के अनुरूप विकसित हो। मुख्य सचिव ने कहा यदि निर्माण के प्रारम्भ में ही कोई परिवर्तन वांछित हो, तो तद्नुसार उसमें संशोधन कर लें, ताकि धन एवं समय का समुचित उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में स्वीकृतियां प्रतीक्षित है, उन्हें तुरंत टीएसी से अनुमोदित कराकर प्रस्ताव शासन को भेजा जाय। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनाये रखने हेतु लगातार अनुश्रवण के निर्देश दिए।

प्रदेश में अपराध, साइबर क्राइम व मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड पुलिस के लिए साल 2019 विगत वर्षों की तुलना में अपराध व कानून व्यवस्था के आंकड़ों को देखते हुए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इस साल पुलिस ने ज्यादातर अपराधिक मामलों का निस्तारण और घटना के बाद प्रॉपर्टी रिकवरी में पिछले सालों की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए अग्रिम राज्यों की सूची में खुद को बनाए रखा।
हालांकि, प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध, साइबर क्राइम व मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसके साथ ही पुलिस के कई सराहनीय कार्य भी इस साल चर्चा में रहे। गौर हो कि प्रदेश में बढ़ते अपराध पुलिस के चुनौती बने हुए हैं।

उद्यमिता विकास केन्द्र सरकार की प्राथमिकता में

समीक्षा

■ राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के कार्यो की केंद्रीय मंत्री ने की समीक्षा

देहरादून। **संवाददाता**

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का डॉ0 महेन्द्र नाथ पाण्डे मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार ने दौराकर संस्थान द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री द्वारा निसबड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

केंदीय मंत्री डॉ0 महेन्द्र नाथ पाण्डे प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

आगमन पर संस्थान की निदेशक डॉ0 पूनम सिन्हा ने उनका स्वागत किया एवं आभार प्रकट कर क्षेत्रीय कार्यालय से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस दौरान निसबड से प्रशिक्षित उद्यमियों द्वारा अपने उत्पाद की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें जूट उत्पाद, खादी उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, एलईडी उत्पाद, सैनेटरी नैपकिन तथा सौन्दर्य प्रसाधन के उत्पादों को प्रदर्शित कर किस प्रकार इससे रोजगार संवर्धन किया जाता है इसकी जानकारी दी गयी।

मंत्री द्वारा संस्थान में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों से वार्ता कर उन्हे मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग करने का भरोसा दिया गया।

इस अवसर पर मंत्री महोदय द्वारा संस्थान के कार्यों की सराहना की गयी। उन्होने कहा कि उद्यमिता विकास केन्द्र सरकार की प्राथमिकता मे है। सरकार के इस कार्य को निसबड जैसे– संस्थानों के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने का कार्य किया जाये।

भाजपा एससी व एसटी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की तैयारी में जुटी

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र सात जनवरी को बुलाया गया है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को अगले 10 साल के लिए जारी रखने के प्रस्ताव को पारित कराया जाएगा। उत्तराखंड में लगभग 21 फीसदी वोट दलित समुदायों का है। इस पर न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस और बसपा की भी नजर रही है। इतना बड़ा वोट बैंक प्रदेश की सत्ता पर काबिज करने के लिए काफी है। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे को बीजेपी 2022 में कैश करेगी। जानकारों के अनुसार भाजपा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव का उत्तराखंड के 2022 के चुनावों में फायदा जरूर उठाना चाहेगी।

मंहगा होगा इलाज

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले सरकारी अस्पतालों में नए साल से इलाज महंगा हो जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड, पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।